वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी

06
अध्याय

वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी

1. आवंटन की स्थिति (सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित खानें)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवंटित की गई 204 कोयला खानों का आवंटन अब कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अब तक कुल 167 कोयला खानों का आवंटन किया गया है। इसमें से 28 कोयला खानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। शेष आवंटित 139 कोयला खानों में से 87 कोयला खानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया गया है, जबकि 52 को आवंटन के माध्यम से आवंटित किया गया है। नीलाम की गई 87 खानों में से 32 खानों को खान खोलने की अनुमति मिल गई है (25 उत्पादन के अधीन हैं)। आबंटित 52 खानों में से 38 खानों को खान खोलने की अनुमति मिल गई है (35 उत्पादन के अधीन हैं)।

कोयला खदानों की स्थिति इस प्रकार है: –

सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित कोयला खदानों की स्थिति								
क्र.सं.	आवंटन का तरीका	अंतिम उपयोग "पावर"	अंतिम उपयोग "एनआरएस"	कोयले की बिक्री	कुल	खान खोदने की अनुमति प्राप्त खाने	गैर–प्रचालन खानें	उत्पादन के अधीन खानें
1	नीलामी	5	16	66	87	32	55	25
2	आवंटन	38	2	12	52	38	14	35
कुल		**43**	**18**	**78**	**139**	**70**	**69**	**60**
एमएमडीआर अधिनियम के तहत आवंटित कोयला खानों की स्थिति								
1	नीलामी	0	0	65	65	3	62	0
2	आवंटन	4	0	1	5	1	4	0
कुल		**4**	**0**	**66**	**70**	**4**	**66**	**0**
कुल योग		**47**	**18**	**144**	**209**	**74**	**135**	**60**

139 सीएमएसपी कोयला खानों में से 70 खानों को खदान खोलने की अनुमति मिल गई है और 60 खानों ने कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया है। 70 एमएमडीआर कोयला खानों में से 4 खानों को खदान खोलने की अनुमति मिल गई है।

नामित प्राधिकारी द्वारा आवंटित कोयला ब्लॉकों से नवंबर, 2025 तक उत्पन्न कुल राजस्व 27776.55 करोड़ रुपये (रॉयल्टी, कर, उपकर आदि को छोड़कर) है।

वित्त वर्ष 2025–26 (31 दिसंबर, 2025 तक) में आवंटित कैप्टिव और वाणिज्यिक ब्लॉकों से कुल कोयला उत्पादन 143.86 मीट्रिक टन है, दिसंबर 2025 में उत्पादन 19.38 मीट्रिक टन है।

2. नामित प्राधिकारी द्वारा एमएमडीआर खानों का आवंटन

कुल 70 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है और नामित प्राधिकारी द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत उन्हें सौंपा गया है।

3. राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और प्रतिनिधि कीमतों की प्रचालन नियमावली

कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीलामी प्रक्रिया में, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई) और प्रतिनिधि मूल्य (आरपी) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सूचकांक की अवधारणा और डिजाइन के साथ–साथ प्रतिनिधि मूल्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा विकसित किए गए हैं। वर्तमान दिशा–निर्देशों में तकनीकी विवरण दिए गए हैं जिनका पालन कोयला मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप एनसीआई और आरपी के संकलन के विभिन्न चरणों में किया जाना है

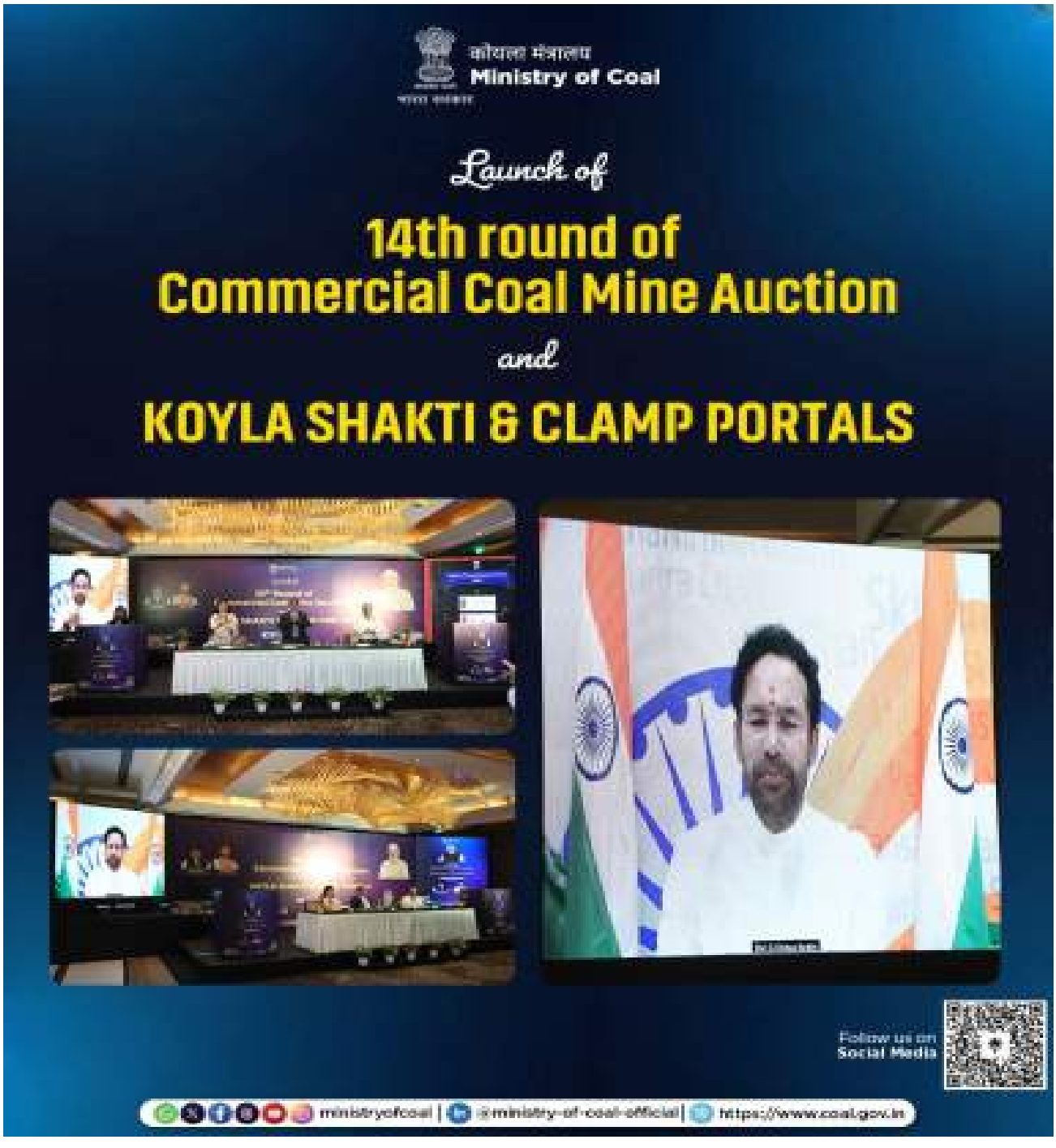

3क. एनसीआई और आरपी की संक्षिप्त सामग्री: एनसीआई एक मूल्य सूचकांक है जो सभी बिक्री चैनलों– अधिसूचित मूल्यों, नीलामी मूल्यों और आयात मूल्यों से कोयले की कीमतों को मिलाता है।

अधिकांश कोयले की बिक्री अधिसूचित कीमतों के माध्यम से की जाती है। नॉन–कोकिंग कोल के लिए, सीआईएल प्रत्येक ग्रेड

के लिए अधिसूचित मूल्य निर्धारित करता है। विनियमित क्षेत्र और गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के संबंध में मूल्य अंतर है। इसके अलावा, लागत को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूसीएल कोयले के लिए अलग–अलग अधिसूचित मूल्य व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, एससीसीएल भी विनियमित और गैर–विनियमित क्षेत्रों के बीच मूल्य अंतर के साथ कोयले के विभिन्न गे्रडों के लिए मूल्यों को अधिसूचित करता है। कोकिंग कोल के संबंध में, सीआईएल की केवल कुछ सहायक कंपनियां ही उत्पादन कर रही हैं। कोकिंग कोल की कीमतों को अधि ासूचित करने की शक्ति सहायक कंपनियों को सौंपी गई है। विनियमित और एनआरएस के लिए कोयले के प्रत्येक ग्रेड के अधिसूचित मूल्य और सीआईएल (डब्ल्यूसीएल को छोड़कर), डब्ल्यूसीएल और एससीसीएल के लिए गैर–कोकिंग कोयले के लिए और विनियमित क्षेत्र के साथ–साथ एनआरएस के लिए विभिन्न ग्रेडों की विभिन्न सहायक कंपनियों के कोकिंग कोल के लिए अधिसूचित मूल्य एनसीआई के साथ–साथ आरपी के उद्देश्य के लिए किए जाएंगे।

अधिसूचित कीमतों पर बिक्री के अलावा, सीआईएल और एससीसीएल विभिन्न प्लेटफार्मों– एमएसटीसी और जंक्शन पर कोयले की ई–नीलामी करते हैं। इस प्रयोजन के लिए, एक विशेष प्रकार के ग्राहक के लिए योजनाओं का एक सेट है। नीलामी प्रत्येक महीने आयोजित की जाती है। इसके अलावा, सीआईएल एनआरएस के लिए लिंकेज नीलामी करता है। एनसीआई और आरपी के प्रयोजन के लिए, नीलामी से विभिन्न गे्रडों के कोयले के इकाई मूल्य (केवल सीआईएल के) पर विचार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए नीलामी का अर्थ ई–नीलामी और लिंकेज नीलामी दोनों है।

एनसीआई और आरपी का तीसरा घटक आयात मूल्य है। दोनों के संकलन के लिए, केवल विनिदष्ट देशों से विशिष्ट प्रकार के कोयले के आयात को ही ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक महीने के लिए, आयात की मात्रा और उसका मूल्य डीजीसीआईएस से एकत्र किया जाएगा और इन दो मूल्यों से, एनसीआई के साथ–साथ आरपी में इसके उपयोग के लिए कोयले के इकाई मूल्य की गणना की जाएगी।

3.ख डेटा संग्रहण: विभिन्न प्रकार के मूल्य डेटा के संग्रह का शुल्क पूरी तरह से डीडीजी कार्यालय पर होता है। इस प्रयोजन के लिए, निदेशक (विपणन), सीआईएल और डीजीसीआईएस को नियमित आधार पर डेटा भेजने के लिए एक पत्र भेजा गया था। डीडीजी को निर्धारित समय–सीमा के भीतर आंकडे एकत्र करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए विपणन प्रभाग, सीआईएल और डीजीसीआईएस के अधिकारियों के साथ बातचीत करनी होती है। कोकिंग कोल की अधिसूचित कीमतों को प्राप्त करने के लिए, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और डब्ल्यूसीएल की कोकिंग कोल कीमतों के लिए सीआईएल के साथ डीडीजी द्वारा नियमित रूप से बातचीत की जाती है, जिनके डेटा इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।

मंत्रालय द्वारा हर महीने एनसीआई संकलित किया जा रहा है। नवीनतम एनसीआई नवंबर, 2025 के महीने में प्रकाशित किया गया था।

4. वाणिज्यिक खनन

वर्ष 2014 में शुरू की गई नीलामी–आधारित व्यवस्था ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी, हालांकि, यह स्वयं के अंतिम उपयोग संयंत्रों में कैप्टिव उपयोग तक सीमित था। इस क्षेत्र को वर्ष 2020 में निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए खोल दिया गया है और वाणिज्यिक खनन की पहली सफल नीलामी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18.06.2020 को शुरू की गई थी और 18 कोयला खानों के आवंटन के साथ संपन्न हुई थी।

वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी दो चरण की ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में आयोजित की जाती है, जिसमें पहले चरण में तकनीकी जांच और प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल है, और दूसरा और अंतिम चरण जहां बेहतर मूल्य प्रस्ताव प्राप्त करने का इरादा है।

वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी प्रतिबंधित क्षेत्रें, उपयोग और मूल्य की पहले की व्यवस्था से पूरी तरह से अलग है। अब, इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं हैं। नीलामी में नियम और शर्तें हैं जो बहुत उदार हैं, जिससे नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलती है।

अग्रिम राशि में कमी, रॉयल्टी के खिलाफ अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के संचालन के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के आधार पर उचित वित्तीय शर्तें और राजस्व साझाकरण मॉडल की अनुमति है।

अब तक अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों में 136 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की गई है (ब्यौरा अनुलग्नक–I में संलग्न है)। उपर्युक्त 136 कोयला ब्लॉकों की सफल नीलामी के माध्यम से कोयला धारक राज्य सरकार को होने वाले अनुमानित लाभ निम्नानुसार हैं: –

क.सं.	राज्य	नीलाम की गई कोयला खानों की संख्या	नीलाम की गई कोयला खदान का संचयी पीआरसी (एमटीपीए'	खान के पीआरसी के आधार पर सृजित वार्षिक राजस्व (करोड़ रुपये)'	पूंजी निवेश (करोड़ रुपये)'	कुल रोजगार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष)'
1	अरुणाचल प्रदेश	2	0.54	278.98	81.50	730
2	असम	2	0.02	38.44	3.60	20
3	छत्तीसगढ़	23	49.51	8479.24	7426.50	66,398
4	झारखंड	38	85.85	9,888.33	12,877.5	1,16,069
5	मध्य प्रदेश	30	23.03	4289.33	3,454.50	31,137
6	महाराष्ट्र	11	6.57	1,192.70	985.50	8,883
7	ओडिशा	26	150.63	18,344.99	22,594.50	2,03,652
8	तेलंगाना	1	4.00	447.01	600.00	5,408
9	पश्चिम बंगाल	3	4.89	371.18	733.50	6,611
	महायोग	**136**	**325.04**	**43330.21**	**48756.60**	**4,39,447**

**कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक नीलामी के भाग 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 के तहत खानों के लिए केवल पूरी तरह से खोजी गई खानों के लाभों की गणना की गई है क्योंकि आंशिक रूप से खोजी गई खानों की पीआरसी उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, वाणिज्यिक नीलामी की किश्त 1 कोयला खानों से लाभों की गणना करते समय, आंशिक रूप से और पूरी तरह से खोजी गई दोनों खानों से लाभ पर विचार किया गया है क्योंकि आंशिक रूप से और पूरी तरह से खोजी गई कोयला खानों दोनों की पीआरसी उपलब्ध थी।*